खण्ड-07 सत्र-04 / अंक-37

सोमवार 20 मार्च, 2023 / 29 फाल्गुन, 1944 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

चौथा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-07 सत्र-04 में अंक 36 से अंक 43 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

राज कुमार

सचिव

RAJ KUMAR

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप-सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-4 सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944(शक) अंक-37

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	8-39
3.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागज़ात	40-41
4.	आउटकम बजट 2022-23	42-49
5.	उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	50-55
6.	सदन में अव्यवस्था	56-58

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-4 सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक) अंक-37

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुआ।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1 श्री अजेश यादव
2 श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
3 श्रीमती ए. धनवंती चंदीला ए.
4. श्री अमानतुल्ला खान
5. श्री अब्दुल रहमान
6. श्री बी एस जून
7. श्री धर्मपाल लाकड़ा
8. श्री दिनेश मोहनिया
9. श्री गिरीश सोनी
10. श्री गुलाब सिंह
11. श्री हाजी युनूस
12. श्री जय भगवान
13. श्री करतार सिंह तंवर
14. श्री मुकेश अहलावत
15. श्री नरेश बाल्यान
16. श्री नरेश यादव
17. श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर
18. श्री प्रलाद सिंह साहनी

19. श्री प्रवीण कुमार
20. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
21. श्री ऋतुराज गोविंद
22. श्री राजेश गुप्ता
23. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
24. श्रीमती राजकुमारी ढ़िल्लों
25. श्री राजेश ऋषि
26. श्री रोहित कुमार
27. श्री शरद कुमार चौहान
28. श्री सोमदत्त
29. श्री शिवचरण गोयल
30. श्री सोमनाथ भारती
31. श्री सहीराम
32. श्री एस के बग्गा
33. श्री विनय मिश्रा
34. श्री वीरेंद्र सिंह कादियान
35. श्री अभय वर्मा
36. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
37. श्री अजय कुमार महावर
38. श्री जरनैल सिंह
39. श्री जितेंद्र महाजन
40. श्री महेन्द्र यादव
41. श्री मदन लाल
42. श्री मोहन सिंह बिष्ट
43. श्री ओमप्रकाश शर्मा
44. श्री पवन शर्मा
45. श्री प्रकाश जारवाल
46. श्री रघुविंदर शौकीन
47. श्री सुरेंद्र कुमार
48. श्री विजेंद्र गुप्ता
49. श्री विशेष रवि

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-4 सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक) अंक-37

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए ।

राष्ट्रगीत-वन्दे मातरम्

माननीय अध्यक्षः माननीय सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। आज माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा जी का जन्म दिन है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ। कितने साल हो गए, कितने साल के हो गए उन्हें स्वयं बता देना चाहिये।

श्री ओम प्रकाश शर्माः आपसे एक साल कम।

माननीय अध्यक्षः मुझे माननीय सदस्यगण, मुझे श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी माननीय नेता प्रतिपक्ष नियम, 251 के तहत अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम-251(1) में यह स्पष्ट लिखा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर

अध्यक्ष की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा अध्यक्ष को यह भी देखना होगा, क्या प्रस्ताव नियम-251(2) के तहत नियमानुकूल है या नहीं, ये स्वयं मैं इस नोटिस की जांच करूंगा और बजट प्रस्तूत होने के बाद अपनी व्यवस्था दूँगा।

माननीय सदस्यगण मुझे कई माननीय सदस्यों से नियम-55 के अंतर्गत अल्पकालीक चर्चा तथा नियम-54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण और नियम-107 के अंतर्गत प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। आज उप-राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है तथा आज ही इसे पारित किया जाना है। अतः कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अलावा किसी अन्य विषय पर चर्चा करना सम्भव नहीं होगा, इसलिए मैं इन सूचनाओं को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। माननीय सदस्यगण दिनांक 18 जनवरी, 2023 को प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों ने हंगामा किया और बोतलों में पानी दिखा कर यह आरोप लगाया की यह यमुना नदी का पानी है और यमुना खतरनाक रूप से प्रदूषित हो गई है। विरोध प्रदर्शन करने वाले सदस्यों ने उन बोतलों को मेरी मेज पर रख दिया। मैंने उस दिन व्यवस्था दी थी कि बोतलों की जांच के लिए दिल्ली जल बोर्ड के पास भेजा जाएगा। मैंने ये भी कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड के अलावा कोई अन्य बाहरी एजेंसी इन बोतलों के पानी की जांच करे। मैंने भी निर्देश दिया था कि दिल्ली जल बोर्ड भी यमुना के पानी की जांच करवाए। दिनांक 19 जनवरी, 2023 को पानी की बोतलें दिल्ली जल बोर्ड को भेजी गई, उनके सैंपल की जांच

दिल्ली जल बोर्ड और सीएसआईआर नीरी द्वारा की गईं दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को रिमाइंडर जारी करने के बाद दिनांक 7 मार्च, 2023 को रिपोर्ट विधान सभा सचिवालय को भेजी गईं हालांकि उन रिपोर्ट को देखने के बाद मैंने दिल्ली जल बोर्ड को इस संबंध में अधिक विस्तृत रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। दिल्ली जल बोर्ड की विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 15 मार्च, 2023 को तब प्रस्तुत की गई जब मुझे इस मुद्दे पर मीटिंग के लिए दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को बुलाना पड़ा। इन रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट ढ़ंग से बताया गया है कि बोतलों का पानी यमुना का नहीं था।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः एक सैकंड मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि पीने का पानी था और उसमें कुछ काला पदार्थ मिलाया हुआ था। यह बहुत गम्भीर मामला है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि विपक्ष के सदस्यों को अनावश्यक सनसनी पैदा करने और सदन को गुमराह करने से आखिर क्या हासिल हुआ। विपक्ष के सदस्यों ने दिल्ली के लोगों में दहशत और अशांति फैलाने का प्रयास किया।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई रिपोर्ट तो सुन लेने दो सदन के सदस्यों को। रिपोर्ट मुझे पढ़ लेने दीजिए, ठीक नहीं है ये बात, रिपोर्ट सुनाई नहीं दे रही है किसी को, आपके हंगामे के बीच में। विपक्ष के सदस्यों ने दिल्ली के लोगों में दहशत और अशांति फैलाने का

प्रयास किया और मुझे बेहद दुख है कि इस कार्य के लिए इस प्रतिष्ठित सदन का दुरूपयोग किया गया। सदन में नियमों का उल्लंघन करके दिनांक 18 जनवरी, 2023 को पानी की बोतलें लाने और प्रदर्शित करने वाले सदस्यों के आचरण के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मैं इस पूरे मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपता हूँ। समिति को इस बारे में भी रिपोर्ट देनी चाहिये की इस मामले में कौन-कौन शामिल थे और पानी कहां से लाया गया। इसके अलावा मैंने अनुभव किया है और ऐसा प्रतीत भी होता है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट देने में विलंब करने और उसको दबाने का प्रयास किया गया। समिति को भी इसकी जांच करनी चाहिये और इस बारे में रिपोर्ट देनी चाहिये, क्या जानबूझ कर ऐसा करने का प्रयास किया गया था। रिपोर्ट एक महीने के अंदर प्रस्तुत करनी होगी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार की रिपोर्ट निंदनीय है। यमुना 200 प्रतिशत ज्यादा प्रदूषित हो गई है।

माननीय अध्यक्ष: एक सैकंड बैठ जाइये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बैठ जाइये। बैठ जाइये, कोई बात नहीं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ये जो रिपोर्ट है, सदन पटल पर माननीय सदस्यों में वितरित कर दी जाए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण विशेष उल्लेख। बिधूड़ी जी आपके लिए उचित नहीं है ये। आपके लिए उचित नहीं है ये। आपने अपनी बात करनी है, समिति को भेज दिया, समिति को दीजिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं, नहीं मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैंने समिति को रैफर कर दिया, नो कमेंटस एट ऑल।

...व्यवधान...

श्री मोहन सिंह बिष्टः सर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। वो 200 परसैंट जो रिपोर्ट दी थी सारी।

माननीय अध्यक्षः आप समिति के सामने रखना। आप मोहन सिंह बिष्ट जी और आप समिति के सामने रखना, आप समिति के सामने रखना। जो रिपोर्ट है समिति के सामने रखना, ठीक है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मत रखिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: 280 श्री अभय वर्मा जी। अभय वर्मा जी पढ़िए मैंने 280 में दिया है। 280 में आपका नाम है, मैं ड्रॉप करता हूँ अगर नहीं पढ़ना है तो। 280 में अभय वर्मा जी। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए। नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। 280 श्री अभय वर्मा जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: अभय वर्मा जी, आप पढ़ना आरम्भ करें।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आखिरी बार रिक्वैस्ट कर रहा हूँ। अभय वर्मा जी मैं आखिरी बार रिक्वैस्ट कर रहा हूँ। बोलने दीजिए, आप पढ़िए।

विशेष उल्लेख (नियम-280)

श्री अभय वर्मा: आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे 280 के तहत लक्ष्मीनगर के मंडावली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, एक लोकहित की समस्या रखने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: भई बातचीत नहीं।

श्री अभय वर्मा: आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मीनगर के अंतर्गत मंडावली स्थित डिस्पेंसरी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस डिस्पेंसरी

के भवन की हालत अत्यंत जरजर होने के कारण यहां से हटाकर कहीं दूर दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया है। इस डिस्पेंसरी के अलग-अलग विभागों में बांटकर, इसे अलग-अलग जगह स्थानांतरित कर दिया गया। बेहतर होता की इसे पुरानी डिस्पेंसरी के पीछे नगर निगम के खाली भवनों में स्थानांतरित किया जाता, इससे मंडावली के लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जब तक पुराने भवन के स्थान पर नया भवन नहीं बनता, तब तक इसके सभी विभागों को नगर निगम के खाली भवनों में स्थानांतरित किया जाए। इस पुरानी डिस्पेंसरी को समाप्त करके इसे पोलीक्लीनिक में बदलने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार के पास लम्बित है। डिस्पेंसरी को कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित करने से लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा हैं। अध्यक्ष जी पिछले 2 वर्षों से जल्द से जल्द पोलीक्लीनिक बनाने का वायदा सरकार कर रही है, यहां तक की बजट भी मिल चुका है, पर काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि लोगों की समस्याओं को देखते हुए जन हित में मंडावली स्थिति पुरानी डिस्पेंसरी के भवन के स्थान पर जल्द से जल्द नए भवन का निर्माण कराया जाए और इसमें शीघ्रातिशीघ्र पॉलीक्लीनिक चालू किया जाए। ताकि वहां के स्थानीय लोगों को जल्द से जल्द और अधिक से अधिक चिकित्सा सेवा का लाभ

मिल सके। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का सदा आभारी रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। विजेंद्र गुप्ता जी।

श्री विजेंद्र गुप्ताः आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से दिल्ली सरकार का ध्यान दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय डीएसयू में फीस में की गई भारी बढ़ोतरी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। भारी फीस वृद्धि के कारण डीएसयू में 25 सौ से अधिक सीटें खाली पड़ी है। सरकार द्वारा गैर जिम्मेदार तरीके से डीएसयू के रि-ब्रांडिंग के विज्ञापनों पर भारी खर्च किया गया। इस सबके बाद भी सीटों का खाली रहना चिंता का विषय है। छात्रा कौशल सीखना चाहते हैं, किन्तु अप्रत्याशित तरीके से सरकार द्वारा डिप्लोमा पाठयक्रमों के लिए फीस को 400 प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़ाकर अचानक छः हजार रूपये से 24 हजार रूपये तक कर दिया गया। वहीं बीटेक और एमटेक पाठयक्रमों के लिए भी फीस 500 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 35 हजार रूपये से एक लाख 81 हजार 500 रूपये कर दी गईं समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को उचित शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और उचित शिक्षा का पूर्ण रूप से व्यवसायिक करण किया जा रहा है। सरकार को इस पर घ्यान देने की आवश्यकता है। रि-ब्राडिंड कौशल विश्वविद्यालय के विज्ञापनों पर दिल्ली सरकार द्वारा किये गए भारी खर्च के बावजूद पाठयक्रमों में नामांकित छात्रों की संख्या उल्लेखित रूप से कम है। मान्यवर ध्यान देने योग्य बात ये है कि मौजूदा

सत्र पहले ही शुरू हो चुका है। 25 सौ से अधिक सीटें अभी भी खाली पड़ी है। गरीब छात्रों के भविष्य पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। गुणवत्ता पूर्ण कौशल भारत की युवा शक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी छात्रों को चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अवश्य मिले। मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय में सरकार द्वारा फीस में की गई भारी वृद्धि के कारण सीटों की उच्च मांग के बावजूद खाली रह गई सीटों के मुद्दे को हल करने का अनुरोध करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही चिंता का विषय है और जो डीएसयू जो बनाया गया, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि कमेटी बनाकर इसकी पूरी जांच करायें, वहां स्थिति क्या है। पूरा हो गया है। ना वहा पॉलिटैक्निक जो थे वो रहे हैं, ना डीएसयू का कोई नया पाठयक्रम प्रारम्भ हो पाया है। पूरा हो गया है। सैंकड़ों करोड़ सरकार ने उसके रेनोवेशन पर खर्च कर दिये लेकिन उसका ना लाभ मिला बल्कि सीटें और कम रह गई, कम हो गई, बच्चों ने दाखिला कम लिया जबकि सरकारी जो पाठयक्रम है जो व्यवस्था है उसमें लोग पहले जाकर दाखिला लेते हैं लेकिन फीस ही इतनी बढ़ा दी गईं तो मेरा आपसे अनुरोध है आपके माध्यम से सरकार से मंत्री महोदया से कि वो इस पर तुरन्त संज्ञान लें और इसको तुरन्त दुरूस्त किया जाए। फीस को फिर से वापिस कम किया जाए और सीटों को भरा जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री मोहन सिंह बिष्ट जी।

श्री मोहन सिंह बिष्टः आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान करावल नगर विधान सभा क्षेत्र की ओर पेयजल की भयंकर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, ये बिल्कुल सत्य है जल ही जीवन है। लेकिन करावल नगर विधान सभा क्षेत्र की आबादी और उसके बराबर मुस्तफाबाद विधान सभा की आबादी। मैं वोटिंग के आधार पर बताना चाहता हूँ आठ लाख के करीब है और करावल नगर विधान सभा में पानी आपूर्ति की बहुत भंयकर समस्या बनी हुई है। सर मैं एक आपसे humble request करना चाहता हूँ। करावल नगर विधान सभा के अन्तर्गत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बने हुए हैं। सोनिया विहार, भागीरथी विहार ये करावल नगर के अन्तर्गत और मुस्तफाबाद विधान सभा के अंदर इन्हीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी की सप्लाई होती है। अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि करावल नगर की जनता को पीने के पानी के लिए एक-एक बूँद के लिए क्षेत्र की जनता तरस रही है। जल बोर्ड के अधिकारियों से बार-बार निवेदन करने के बाद भी पानी की आपूर्ति को बढ़ाया नहीं जा रहा है। ये ही नहीं जिन जो दो विधान सभाओं को पानी की सप्लाई की जाती है वहां सिर्फ ढाई एमजीडी पानी की आपूर्ति की जा रही है और जबकि उन क्षेत्रें के लिए दस से ले करके बारह एमजीडी पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना कि सरकार बार-बार कहती कि हम

चौबीस घंटे हम पानी की उपलब्धि करायेंगे लेकिन मेरी विधान सभा क्षेत्र के अंदर सिर्फ आधा घंटा पानी आता है और आधे घंटे के बाद भी पानी फिर से सप्लाई बंद हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि करावल नगर विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की आपूर्ति को तुरन्त बढ़ाया जाए जिससे जनता प्यासी ना रहे। मुझे आपने बोलने का समय दिया, आपका आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः शिवचरण गोयल जी।

श्री शिवचरण गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी मैं आपका ध्यान मेरे निर्वाचित क्षेत्र मोती नगर विधान सभा की ओर दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, ये जो गम्भीर समस्या है आज मैं सदन में रख रहा हूँ। ये मेरी विधान सभा की नहीं पूरी दिल्ली की समस्या है। आज पूरी दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड लाभार्थी हैं और मोती नगर विधान सभा की लगभग 35 परसेंट जनसंख्या कलैस्टर में रहती है। जबसे नोट बंदी हुई, जीएसटी लागू हुआ है तब से सभी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है और उनका जीवन यापन करना बहुत कठिन हो रहा है। मेरे क्षेत्र मोती नगर विधान सभा में और पूरी दिल्ली में गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाता था। उसमें एक योगदान प्रधान मंत्री राशन योजना का था और दूसरा योगदान मुख्यमंत्री राशन योजना का था। जिसमें जनता को पांच किलो प्रति व्यक्ति उन्हें प्रधान मंत्री राशन से दिया जाता था और पांच किलो

प्रति व्यक्ति मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी से प्राप्त होता था, परन्तु 2023 जनवरी से प्रधान मंत्री कोष द्वारा राशन बंद कर दिया गया और अब उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल द्वारा मुफ्त राशन प्राप्त हो रहा है। जिसके कारण मोती नगर विधान सभा और दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। अध्यक्ष जी, जहां पर हम राशन के माध्यम से पूरी पूर्ति करते हैं वहां पर राशन बंद कर दिया गया। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ पूरे संसार में एक तालिबान आतंकवादी संगठन है जिसने हमारे हवाई जहाज को कंधार में हाईजैक करके सैंकड़ों लोगों को बंदी बनाया था और उसमें हमारे पसेंजर की हत्या भी की थी। उस आंतकवादी संगठन को फरवरी 2000 के बजट में सैंकड़ों करोड़ रूपये की सहायता बजट में दी जा रही है और हमारी दिल्ली का गरीबों का राशन बंद किया जा रहा है। तो दिल्ली की जनता प्राथमिकता है या तालिबान तो ये एक गम्भीर ईशू है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है की गरीबों का राशन बंद न किया जाए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप अपना पढ़िये, आप अपना पढ़िये-पढ़िये, पूरा करिये।

श्री शिवचरण गोयलः इस राशन को दोबारा शुरू किया जाए आम आदमी को राहत मिले आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षः श्री संजीव झा जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः इसमें चर्चा नहीं है बिधूड़ी जी, कोई चर्चा नहीं है इसमें कोई नियम नहीं है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं कोई चर्चा नहीं है चलिए संजीव झा जी। 280 में आप भी बोलते हैं तथ्यों से परे चीजें होती हैं चलिए।

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो दिल्ली के विधायक हैं या भूतपूर्व विधायक हैं या दिल्ली सरकार में जो कार्यरत या सेवारत अधिकारी हैं उनको अगर आप आपातकाल की स्थिति में बाहर जाते हैं और बीमार पड़ते हैं तो उनको वहां जो ईलाज कराते हैं उसके बाद जो रिंबर्समेंट होता है उसमें बहुत कांट-छांट रिंबरर्समेंट होता है और इससे बहुत नुकसान होता है सभी अधिकारियों का। डीजीएचएस में यह प्रावधान है कि अगर कोई बाहर जाए और बीमार पड़ जाए तो उसका ईलाज सीजीएचएस अस्पतालों में वहां के इंपेनल रेट पर किया जाना चाहिए लेकिन कभी स्वास्थ्य विभाग ने इसका संज्ञान नहीं लिया जिससे आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है। तो इस संबंध में मेरा आपसे यही अनुरोध है और आपके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को भी मैं

जानकारी देना चाहता हूँ मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं कि अगर कोई बाहर जाता है इस तरह के जो मेडिकल लाभार्थी हैं अगर वो बाहर जाते हैं तो चाहे आपातकाल की स्थिति हो या नार्मल स्थिति हो उनका ईलाज जो इंपेनल रेट है उसी इंपेनल रेट पर किया जाए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के जो एचओडी हैं उसकी एक आप मीटिंग बुला लें और उनको निर्देशित करें ताकी ये जो आर्थिक नुकसान यहां के लोगों को हो रहा है वो आर्थिक नुकसान न हो।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद।

श्री ऋतुराज गोविंदः इसमें एक चीज बोलनी है अध्यक्ष जी जो हास्पिटल दिल्ली के अंदर में जो दिल्ली के प्राइवेट हास्पिटल हैं कोविड से पहले वो कैशलेस फेसिलिटी देते थे डीजीएचएस में लेकिन कोविड के बाद उन्होंने कैशलेस फेसिलिटी बंद कर दी है। अगर मान लीजिए किसी माननीय सदस्य के परिवार में कोई व्यक्ति बहुत सीरियसली बीमार है तो वो तो एक लाख रुपया एडवांस में जमा करो तभी ईलाज कराएंगे। अब किसी के पास एक लाख नहीं होगा तो क्या ईलाज नहीं करेंगे वो तो पहले कैशलेस फेसिलिटी होती थी जो की बाद में बंद कर दिया गया है उसको फिर से चालू करने की भी जरूरत है इस स्कीम के तहत।

माननीय अध्यक्षः जितेन्द्र महाजन जी।

श्री जितेन्द्र महाजनः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे 280 पर बोलने का मौका दिया। मैं जिस

समस्या की ओर बोलना चाह रहा हूँ वो रोहताश नगर ही नहीं पूरी दिल्ली की समस्या है। नई शराब नीति आने से पूर्व रोहताश नगर विधानसभा में सिर्फ 4 शराब के ठेके थे उनमें से 3 ठेके एक मॉल के अंदर थे और 1 शराब का ठेका आबादी से दूर था। नई नीति आई उसके अंदर अनेक शराब के ठेके खोले गये घोटाला पकड़ा गया और वो ठेके निरस्त हुए मगर उसके बावजूद अब जो सरकारी ठेके खोले जा रहे हैं रोहताश नगर विधानसभा में अभी तक 7 ठेके आबादी के बीच में खोल दिये गये हैं और ठेके खोलने की योजना चल रही है। मेरा माननीय अध्यक्ष जी और सभी सदस्यों से ये अनुरोध है कि रेवेन्यू कमाने के लिए ये सब क्या किया जा रहा है और दुख की बात तो यह है कि इन शराब के ठेकों के साथ ओयो होटल भी खुल गये हैं। हमारे इलाके में दुर्गापुरी, हरदेवपुरी, चंद्रलोक ऐसी अनेक जगहों पर जहां शराब के ठेके खोले हैं उनके बिलकुल साथ वाली बिल्डिंग में या उनके ऊपर ओयो होटल खोल दिये गये हैं और हमारा इलाका माननीय अध्यक्ष जी न वहां लालकिला है न वहां ताजमहल है यानी पर्यटक वहां आता नहीं है कोई इंडस्ट्रियल एरिया वहां पर है नहीं, कोई व्यापारी आता नहीं है।

माननीय अध्यक्षः महाजन जी आप जो बोल रहे हो वो इसमें लिखा नहीं है।

श्री जितेन्द्र महाजनः हां जी।

माननीय अध्यक्षः जो आप बाद में बोल रहे हो।

श्री जितेन्द्र महाजनः मैं समझा रहा हूँ साहब।

माननीय अध्यक्षः वो समझ में आ गया सब सदस्य समझदार हैं।

श्री जितेन्द्र महाजनः तो मेरा कहना यह है अध्यक्ष जी जब वहां पर्यटक नहीं है, वहां व्यापारी नहीं है तो उन ओयो होटलों में कौन लोग आ रहे हैं, गैर-कानूनी धांधे शुरु हो गये हैं और मेरा आपसे अनुरोध है की इन ओयो होटलों की जांच कराई जाए और पूरी दिल्ली में सभी सदस्य सहमत होंगे की पूरी दिल्ली में ओयो होटल्स के नाम पर जो अययाशी के अड्डे चल रहे हैं इनको बंद कराया जाए और दिल्ली के अंदर आबादी के बीच में शराब की दुकानें न खोली जाएं मैं ये इस सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज गोविंद जी।

श्री ऋतुराज गोविंदः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र का एक ज्वलंत मुद्दा उठाने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, किराड़ी विधानसभा क्षेत्र पूरी दिल्ली के अंदर में एकमात्र विधानसभा है जो 99 प्रतिशत अनॉथराइज कालोनी है और अनॉथराइज कालोनीज खेती की जमीन में बसी हैं। खेती की जमीन अध्यक्ष महोदय 3 तरह की होती है एक हम लोग बिहार में बोलते हैं ऊपर की खेत जिसमें सब्जी की खेती होती है। एक होती है बिचल की खेत उसके अंदर में मोटा अनाज होता है।

एक होता है सबसे नीचे जिसको चौर बोलते हैं हम लोग बिहार में चौर का मतलब होता है जहां पर धान की खेती होती है जिसको आप लोग जीरी बोलते हैं। वहां पर नेचुरली पानी लगता है बारिश के दौरान और उसमें जो है सो कादो, कादो करके उसमें धान लगाते हैं तो चौर हो गया वो तो अध्यक्ष महोदय हमारे क्षेत्र के अंदर में जो अगर-नगर इलाका है या इंदर इन्क्लेव इलाका है या प्रेमनगर थर्ड है या प्रेमनगर सेकेंड का इलाका है ये सबसे नीचे वाले खेत में बसा चौर में बसा। कोई प्रवासी मजदूर जो 5 हजार, 7 हजार रुपया महीना अपना हड्डी गलाकर कमाता है वो बेचारा अपना उस समय में 100 रुपये गज, 200 रुपये गज, 300 रुपये गज उसने एक प्लाट खरीद लिया 25 गज का, 30 गज का और 35 गज का उसमें किसी भी तरीके से कच्चा-पक्का मकान अपना बनाकर के रह रहा था उसको नहीं पता था ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है उसको नहीं पता था सीवरेज सिस्टम क्या होता है। उसके लिए ड्रेनेज का मतलब था वो छोटा सा गड्ढ़ा करके एक सोखता बनाता था जिसमें घर का पानी चला जाता था उसी से वो बेचारा काम चलाता था मेहनत-मजदूरी से नमक रोटी खाता था लेकिन जब सरकारी की अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी बनी जो की जरूरी भी था और सरकार ने तय किया कच्ची कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं हमें देनी है पीने के पानी की लाइन बिछानी है, सीवर की लाइन बिछानी है, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करना है तो जो सबसे नीचे खेत था जिसको चौर बोलते हैं जब उसमें ड्रेनेज सिस्टम के साथ जब

सड़कें बनाई गईं तो 7-7, 8-8, 9-9 फुट की सड़क हो गईं अब उस आशियाना गरीब आदमी का आशियाना तो डूब गया और ऐसा डूबा, ऐसा डूबा की 5 हजार, 7 हजार हड्डी गलाकर कमाने वाला मजदूर उसको ठीक नहीं करा सकता है।

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी कन्क्लूड करिये, कन्क्लूड करिये।

श्री ऋतुराज गोविंदः तो मेरा देखिये इस बात को समझने के लिए ये भूमिका जरूरी है अध्यक्ष महोदय। मेरा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से एक ही चीज निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से की कच्ची कालोनियों में जो 25 गज, 30 गज, 35 गज के खासकर के लो-लाइन इलाके में लोग रहते हैं आप उसका सर्वे करा लीजिए, आप किसी की रिपोर्ट मत मांगिये लेकिन जिस बेचारे का मकान का इतना नुकसान हो चुका है, जो बेचारा लोकल फाइनेंसर से कर्जा लेकर के अपना कच्चा-पक्का मकान बनाया वो दोबारा मकान नहीं बना सकता है क्योंकि वही कर्जा अगर चक्रवर्ती ब्याज चुकाने में उसकी जिंदगी बीत गई कम से कम उस गरीब आदमी को जो 25 गज, 30 गज, 35 गज का मकान जो सरकारी योजना की वजह से डूब गया है उसकी सरकारी मुआवजा नहीं कम से कम सरकारी सहायता जरूर किया जाए ऐसी अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी के अंदर में चीजों को इन्क्लूड किया जाए मेरा आपके माध्यम से यही कहना है और यह मसला केवल किराड़ी का नहीं है ये पूरी दिल्ली की कच्ची कालोनियों का है मेरा हाथ जोड़कर के आपसे निवेदन है की ऐसे गरीब प्रवासी लोगों को प्लीज बचा लीजिए

उनको डूबने मत दीजिए, बर्बाद मत होने दीजिए नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी बर्बाद हो जाएगी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः जरनैल सिंह जी, जरनैल सिंह जी अनुपस्थित। श्री जय भगवान जी।

श्री जय भगवानः माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे 280 पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय मैं आज बहुत ही अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोल रहा हूँ कि पिछले तीन वर्षों से लगातार मैं हमारी जो डीएम नार्थ आर. मेनका जी हैं और जो हमारे एसडीएम हैं उनसे पिछले तीन वर्षों से लगातार कोर्डिनेट कर रहा हूँ जनता के जो विकास कार्यों के लिये, जनता के हित के कार्यों के लिये और पिछले तीन वर्षों से वो लगातार मीटिंग हो रही है लेकिन कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है लगातार मैंने बरवाला के किसानों को लेकर के कई बार दस बार उनके साथ मीटिंग की लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला अध्यक्ष महोदय। नांगल, औचंदी, हरेवली में डिमार्केशन के लिये दस बार में उनसे मिला लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला अध्यक्ष महोदय, किसानों के उजाड़े जाने के मुआवजे को लेकर के मैंने कई बार उनसे मीटिंग की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला अध्यक्ष महोदय और उनके द्वारा लगातार इलाके के अंदर अवैधा कब्जे कराये जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय कृषि भूमि पर लगातार अवैधा कब्जे हो रहे हैं उनके द्वारा और अध्यक्ष महोदय जैसे की टाटा पावर की कोई सर्वे आती है सर्वे को लेकर के छः-छः महीने

बैठ जाते हैं कोई भी कार्य करने को राजी नहीं है ना ही एसडीएम ना ही एडीएम ना ही डीएम। अध्यक्ष महोदय, लगातार इलाके के अंदर submersible लगवाकर के अवैध वसूली की जाती है डीएम, एसडीएम के द्वारा जबकि जनता के अधिकारी हैं ये जनता के लिये काम करने के लिये आये हैं लेकिन जनता को कोई काम नहीं करते लगातार हम लोग बोलते रहते हैं की जनता के हितों के कार्य को करना चाहिये जैसे की अगर रोड़ पर अगर पीडब्ल्यूडी के मेन रोड़ पर किसी ने कब्जा कर लिया हमने कहा की डीटीएफ से इसको हटवा दो एसटीएफ से इसको हटवा दो तो उनके कानों पर जूँ नहीं रेंगती वो कहते हैं की जी हमारे तो उसमें आती नहीं हम तो कुछ कर ही नहीं पायेंगे और जहां पर उनको पैसा कोई नहीं देगा अवैधा वसूली नहीं देगा तो उसका तुरंत तोड़ देंगे तो अध्यक्ष महोदय मैं ये सदन में इसलिये लेकर के आया हूँ की लगातार पिछले तीन वर्षो से मैं लगातार उसके बारे में बोल रहा हूँ लेकिन कोई भी कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जैसे उनके द्वारा सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कराया जा रहा है चाहे वो फोरेस्ट की ज़मीन है, चाहे वो कृषि भूमि है, चाहे वो ग्रामसभा की ज़मीनें हैं लगातार जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं उनकी शह पर सारे काम हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय सारे जो-जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है और दूसरा अभी बीच में एक पिटिशियन कमेटी की हमारी मीटिंग हुई उस कमेटी के अंदर अध्यक्ष महोदय हमारे पिटिशियन कमेटी के

चेयरमैन और हमारे जो अन्य सदस्यों द्वारा जब वहां के जो डिवकॉम और डीएम और एसडीएम को उनको बोला गया इलाके के बारे में तो उसके बाद तो तीन-चार मीटिंगों में वो आये भी नहीं और फोन भी उठाना बंद कर दिया अध्यक्ष महोदय तो अध्यक्ष महोदय ये जनता से जुड़े हुये मामले हैं अगर अधिकारी आकर के अगर कार्य नहीं करेंगे जनता के तो कैसे चलेगा। अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है सदन के माध्यम से की ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये जो जनता के काम को रोकते हैं, धन्यवाद, जय हिन्द।

माननीय अध्यक्षः प्रमिला टोकस, अजय महावर जी।

श्री अजय कुमार महावरः आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका आभार 280 में मुझे विषय उठाने का मौका मिला। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय समाज कल्याण विभाग और महिला एंव बाल विकास विभाग से मैं उठाना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्गों को विधवाओं को और दिव्यांगजनों को जो पेंशन दी जाती है और ये सवाल मैंने भी सदन में उठाया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जो पेंशन दी जाती है उनकी यदि मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद सरकार तुरंत उस पेंशन की जारी की हुई जो राशि है सपोज़ किसी का 10 हजार, 8 हजार, 5 हजार रह गया बैंक के खाते में तुरंत उसको जब्त कर लिया जाता है बैंक के माध्यम से, मुझे लगता है यह असंवेदनशील और अमानवीय है इस पर सरकार को मंत्री जी को आपके माध्यम से मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ की वो

क्योंकि कई बार उनकी मृत्यु के समय भले ही कुछ धानराशि बच जाती है लेकिन बड़ी धानराशि उन पर कर्ज भी हो सकता है किसी किराने वाले का किसी दूध वाले का पैसा बाकी हो सकता है तो सरकार इस पर ध्यान करे क्योंकि बाद में उसके परिजनों पर उसका बोझ पड़ता है कम से कम जो राशि पेंशन की बुजुर्गों को दिव्यांगों को और विधावाओं को हम जारी करते हैं उसको जब्त ना करें वापस ये मुझे बिल्कुल असंवेदनशील लगता है मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ की इसे वापस ना लिया जाये, जब्त ना किया जाये इस राशि को उसके परिवारजनों को इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाये साथ ही सरकार से मैं ये पुरज़ोर मांग करता हूँ की सरकार वृद्धा पेंशन जो काफी लम्बे समय से लम्बित है और माता-पिता समान बूढ़ी आंखें हैं इसकी राह देख रही हैं सूनी हैं आप जल्द से जल्द सरकार आपके माध्यम से बुजुर्ग पेंशन को जारी करें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अखिलेश पति त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्र के से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मुझे मौका दिया है अध्यक्ष महोदय ये मामला सब-रजिस्ट्रार ऑफिस का है और मेरी विधानसभा बगल में दिलीप भाई बैठे हैं उनकी विधानसभा, वज़ीरपुर विधानसभा, आदर्श नगर विधानसभा में कोई सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं है इवन दैन उत्तरी जिला का जो सब-रजिस्ट्रार ऑफिस है वो नॉर्थ वैस्ट डिस्ट्रिक के

एक किराये की बिल्डिंग में चल रहा है और वो बिल्डिंग चौथे और पांचवें मंजिल पर स्थित है मैं माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ 280 के माध्यम से की उस चौथी और पांचवीं मंजिल पर जो बुजुर्ग लोग हैं वो जा नहीं पाते रजिस्ट्री के लिये इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको, आये दिन उसका लिफ्ट खराब रहता है जबकि लगभग 5-6 साल पहले ही इस सब-रजिस्ट्रार ऑफिस को उत्तरी जिले में ही शिफ्ट करने के लिये प्रस्ताव गया था ढका में पटवारघर तैयार होकर तैयार हो गया बनकर के दिलीप भाई के यहां और उसको वहां प्रस्तावित था की वहां पर शिफ्ट कर दिया जायेगा अभी तक वो वहां पर लाया नहीं गया और जो बिल्डिंग है जो उत्तरी-पश्चिमी जिले में चल रही है अगर कहीं नॉर्थ के डीएम से कहा जाये की भई आपका सब-रजिस्ट्रार ऑफिस ठीक काम नहीं कर पा रहा है बुजुर्गों को बहुत दिक्कत है, दिव्यांगों को बहुत दिक्कत है चौथी-पांचवी मंजिल में जाने पर तो जवाब होता है जिला अधिकारी का की यह बिल्डिंग और यह ज्यूरिडिक्शन क्षेत्र हमारे क्षेत्र में नहीं पड़ता उसका डीएम कोई दूसरा है कार्यालय हमारा है हम उस बिल्डिंग में कुछ कर नहीं पाते तो अध्यक्ष महोदय ये लगभग 20 लाख लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो लोग आये दिन इतना बड़ा रेवेन्यु सरकार को मिलता है अध्यक्ष महोदय इससे लेकिन बुजुर्गों के लिये दिव्यांगों के लिये वहां कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है सरस्वती बिहार में भी डीएम ऑफिस में भी वहां भी एक बहुत बड़ा जगह खाली है वहां भी शिफ्ट

किया जा सकता है और सबसे ज्यादा suitable की उत्तरी जिले का सब-रजिस्ट्रार ऑफिस ढक्का में जो पटवारघर पैसा लगाकर बनकर तैयार हो गया है उसमें इसी महीने में महीने भर में अंदर-अंदर उसको शिफ्ट कर दिया जाये ताकि दिव्यांग व्यक्तियों को और बुजुर्गों को जो जाकर के टैक्स देते हैं हम लोगों को उनको राहत मिल पाये, बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान गौतम जी, राजेन्द्र पाल गौतम जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने नियम 280 में मुझे क्षेत्र की समस्या को रखने का मौका दिया जैसा की आप जानते हैं की आपकी विधानसभा और मेरी विधानसभा के बीच में जो डिवाइडर है सीमापुरी डिपो के बगल में रोड़ नंबर-70 पर वहां पीडब्ल्यूडी के रोड़ को लगभग पूरा इन्क्रोच करके कूड़े को सेग्रीगेट करने का काम कुछ लोग करते हैं और वो पूरा रोड़ ही लगभग उन्होंने कब्जा कर लिया है बसों के आने-जाने पर भी दिक्कत है ट्रैफिक जाम रहता है इसी तरह मेरी आपकी विधानसभा के बीच में जो डिवाइडर है कब्रिस्तान रोड़ दिलशाद कॉलोनी का इधार वाले पार्ट के इस साइड में जहां से ई-44 की झुग्गियां हैं एक वो और एक सुरक्षा नर्सिंग होम वाला रोड़ उन दोनों रोड़ को रोड़ काफी चौड़े हैं कम से कम मेरे ख्याल से 60-70 फीट चौड़े रोड़ हैं दोनों लेकिन दोनों रोड़ पर गाड़ी तो दूर है पैदल निकलना भी मुश्किल है। वहां भी वो कूड़ा सेग्रीगेट करने का काम पूरे रोड

पे फैला के, पूरे रोड पर लगभग कब्जा है, तो कूड़ा सेग्रीगेट करना वो भी रोड के ऊपर, इस समस्या से क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हैं। लगातार हम लोग को अप्रोच करते रहते हैं। हमने डीएम को लेकर एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर्स को लेकर पीडब्ल्युडी के अधिकारियों को लेकर, सारे अधिकारियों को लेकर कई बार वहां उन रोड को खाली कराने की कोशिश की, लेकिन वो रोड पर अभी भी कूड़ा लगातर सेग्रीगेट हो रहा है और पैदल निकलने की भी जगह नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करता हूँ कि या तो उन रोडों को पूरी तरह उनसे खाली कराया जाए और संभव हो तो उनको कोई वैकल्पिक जगह मुहैया कराया जाए। उनसे किराया लिया जाए, वे लोग देने को तैयार है। कम से कम लोगों के निकलने का रास्ता तो क्लीयर हो और इससे साथ साथ में एक चीज आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, हम सभी सदन के सम्मानित सदस्य अपनी क्षेत्र की समस्याओं को नियम 280 के तहत लगाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 280 के तहत लगाने का कोई क्या हमें फायदा है या केवल हम अपने क्षेत्र की जनता को संतुष्ट कर दें कि हमने 280 में यहां का मुद्दा उठाया। इसमें कार्यवाही हमें होती दिखती नहीं हैं। आठ साल से ज्यादा हमें सदन का सदस्य बने हो गए। पिछली सरकार में रहे, इस सरकार में भी हैं और सम्मनित सदस्य सब अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं। हम अनेकों कमेटियां बनाई हुई हैं दिल्ली की विधान सभा की, क्या इसपर भी कोई कमिटी बनाई जा सकती है कि जो

280 के तहत कार्यवाही हुई है या नहीं हुई है। संबद्ध अधिकारी अगर कार्यवाही नहीं करते हैं तो उनको बुलाकर वहां कम से कम पूछा जाए कि भी भई ये क्या सारे सम्मानित सदस्य क्या टाइम-पास कर रहे हैं यहां बैठ कर जो आपके क्षेत्र की मुद्दे उठाते हैं और आप कोई भी उसपर कार्यवाही नहीं करते। आखिर हम ये मुद्दा उठा क्यों रहे हैं। सदन का भी पैसा जा रहा है, जनता के पैसे से सदन चलता है और हम मुद्दे उठाए और मुद्दे पर कोई हल न निकले तो लोग भी धीरे-धीरे कहते है जी ये उठते रहते हैं, होता तो कुछ है नहीं, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ, नियम 280 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित हों, इसके लिए कोई न कोई कमेटी आप बनाएं, जो रेगूलर 280 पर भी ध्यान रखें अधिकारियों को बुलाकर कि उसपर कार्यवाही कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, जय हिन्द, जय भारत।

मननीय अध्यक्षः माननीय गौतम जी को मैं जानकारी में देना चाह रहा हूँ। जितने 280 में यहां आते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनपर एक्शन लेता हूँ और माननीय सदस्यों को मालूम भी होगा। फिर भी कोई अगर रह जाता है तो मुझे लिखकर दे सकते हैं। उन समस्याओं को निश्चित रुप से उस विभाग के साथ संबंधित विभाग के साथ रखा जाता है।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः ये सम्मानित सदस्य सारे बता देंगे, चाहे सत्ता पक्ष हों, चाहे विपक्ष हों, उसपर कार्यवाही नहीं होती,

रिजल्ट नहीं आता सर। बिल्कुल रिजल्ट नहीं आता। हम पूरी तरह किल हैं। हम लगातार उठा रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है।

मननीय अध्यक्षः जिन सदस्यों को ऐसा लगता है कि मेरी समस्या पर कार्यवाही नहीं हुई है, जोमैंने 280 में उठाया था तो वो मुझे लिखकर दे सकता हैं मैं उस पर..।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अध्यक्ष महोदय कार्यवाही की बात कर रहे हैं, 280 में जो मैंने नोटिस दिया, उसको आपने रद्द कर दिया।

...व्यवधान...

मननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी मैं आपकी जानकारी में देना चाह रहा हूँ 280 का पहले रूलिंग पढ़ लिजिए, उसमें क्या समस्याएं उठायी जा सकती, फिर मुझसे बात करियेगा। रूल को पढ़िए आप। आप एल.ओ.पी हैं। बैठ जाईए आप। आप पढ़ लिजिए उसको, 280 को पढ़िये पहले। 280 को पढ़िये पहले नियम को। श्री गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय और उनका भी धन्यवाद जो आज 280 बोलने के लिए आये नहीं, जो हमारा नंबर पड़ गया। बिधूड़ी जी देखिये जरा, हमारे यहां बड़ी दिक्कत है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पर ग्रामीण क्षेत्र में और आज ये सफर वही से शुरू होता है, जहां खत्म हुआ था। आपने ही इसका

फैसला कराया था 2019 में, मटियाला विधान सभा के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, विशेष तौर पर मैं गांव का नाम quote कर रहा हूँ:- रावता, झुलझुली, घूमनहेड़ा, सारंगपुर सारंगपुर, झटिकरा, शिकारपुर, कांगनहेड़ी, जो नजफगढ़ ड्रेन के साथ सटे हुए गांव हैं। इन गांव के अंदर हर रोज बिजली विभाग द्वारा लाखों रुपए की इंफोर्समेंट के केस बनते हैं। दो एकड़, एक एकड़ के किसान के ऊपर पांच-पांच, सात-सात लाख रुपए के चोरी के एक केस बनाये जाते हैं फिर उसके बाद उनको लोक अदालत में बुलाया जाता है और उसको फिफ्टी परसेंट में छोड़ने के लिए उनके ऊपर दवाब बनाया जाता है कि चलो आपको फिफ्टी परसेंट छोड़ देते हैं। दो एकड़ के अंदर मुश्किल से 50 हजार रुपए साल में बचते हैं, ये किसानी करने के बाद। मेरा आपको याद भी होगा और आपने 280 में इसका निराकरण कराया था याद होगा कि कैलाश गहलोत जी और सतेन्द्र जैन जी की आपस में भिड़ंत भी हुई थी सदन के अंदर इस मामले में और तब जाके ये हल हुआ था। इसमें दो मामले: एक तो ये है कि जो फिक्स जो रेट है पर किलोवाट का ये हमेशा 20 रुपए किलोवाट रहा है किसानों के ऊपर, जो एग्रीकल्चर कनेक्शन है। लेकिन इसको दोबारा से 120 कर दिया गया है। ठीक वैसे ही जैसे 2018 में 20 से 120 कर दिया गया था, अब दोबारा वो आपने ठीक कराया था इसी सदन में कराया था वो 20 रुपए हो गया था। अब दोबारा से बीएसईएस ने उसको 120 रुपए कर दिया पर किलोवाट फिक्स जो रेट होता है, जोकि किसानों का 4 से 5 महीने जो

मोटर है वो यूज होते हैं खेती-बाड़ी में पानी जो चलाते हैं। सात महीने वो बंद रहती हैं। अब आप सोचिए किसी किसान का अगर 10 किलोवाट का कनेक्शन है तो उसके 1200 रुपए हर महीने आने ही आने हैं, जो कि बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल गलत हैं, तो एक तो इसको हमारी बहन जी बैठी हैं यहां पर मंत्री महोदया जी। आप को बड़ी समस्या आने वाली है अगर आपने हमारा समाधान नहीं किया तो किसानों के बीच में हम आपको लेकर जाएंगे। ये बड़ा गंभीर मामला है तो एक तो इसको आप वापस 20 रुपए पर किलोवाट कर दें तो सभी ग्रामीण क्षेत्र के किसान जो हैं, आपके बहुत ही आभारी रहेंगे।

दूसरा ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये जो इंफोर्समेंट के केस बनाये जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, इसके ऊपर संज्ञान लें। बीएसईएस से इसका जवाब मांगा जाए और जवाब इस तरह से मांगा जाए, हालांकि मैंने इसको स्टार क्वेश्चन में भी लगाया हुआ है और आज तक हालांकि जवाब मिला भी नहीं है कि कितने लोगों के ऊपर चोरी के छापे डाले गये और कितने पैसे की वसूली की गयी। आज तक बीएसईएस इन जवाबों से बचता रहा है तो इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए लेकिन इन सारी समस्या का एक समाधान है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अंदर और कई राज्यों के अंदर किसानों के रेट फिक्स कर रखे हैं। फिक्स हर मोटर के ऊपर 10 किलोवाट की अगर मोटर चल रही है तो उसका फिक्स कर रखा है 700 रुपया, 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो न तो चोरी

होगी, पैसा भी आएगा और किसान चोरी करने पर मजबूर क्यों हैं आप ये सोचिएगा कि जो रेट है बिजली के उसके हिसाब से अगर वो चलाते भी हैं, तो सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उसकी इन्कम होगी न वो भी बीएसईएस के आफिस में डाल के आ जाएगा। एक पैसा नहीं बचा सकते हैं, वो मजबूर हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है माननीय मंत्री महोदया से कि इस बारे में सोचिएगा कि अगर हम ये फिक्स किलोवाट के हिसाब से कर दें तो पर मोटर के हिसाब से कर दें, पर कनेक्शन के हिसाब से कर दें तो यकीन मानना कि दिल्ली के किसान हमेशा इस सरकार का आभारी रहेंगे क्योंकि जब जब किसानों के ऊपर मुसीबत आयी है तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल जी ने चाहे वो फसल बर्बादी का मुआवजे की बात हो तो 20 हजार पर एकड़ देकर हमने पूरे हिन्दुस्तान का एक इतिहास रचा इस विधान सभा के अंदर तो मैं चाहूँगा कि इस विषय को भी गंभीरता से लेते हुए और जो कनेक्शन हैं, उनको फिक्स कर दिया जाए, रेट जो है बिजली की दरें जो फिक्स कर दी जाए ताकि किसानों को किसी तरह की समस्या न हों। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

मननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। नरेश यादव जी।

श्री नरेश यादवः अध्यक्ष जी धन्यवाद जो आपने मुझे यहां बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं गुलाब सिंह जी की बात को सेकेंड करता हूँ कि किसानों का अगर ये जो चार्जेज हैं,

इसको फिक्स कर दिया जाए तो उनके लिए बहुत राहत मिलेगी, अध्यक्ष जी। उसके पश्चात् अध्यक्ष जी मैं आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी, जो हमारे नये मंत्री बने हैं, उनको भी मैं मुबारक देना चाहता हूँ इस सदन के अंदर। साथ में आज सोमनाथ भारती जी, यहां आये नहीं हैं, वो वाईस चैयरमेन जल बोर्ड बने हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सौरभ भाई ने जल बोर्ड में बहुत अच्छा काम किया। सभी विधायकों के साथ मीटिंग करते थे और बहुत अच्छे तरीके से जल बोर्ड की समस्याओं को उठाया और अब मैं सोमनाथ भारती जी से भी यही निवेदन करूंगा कि हम सब विधायकों की जो जल बोर्ड की समस्या अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, उसको बहुत अच्छी तरह से वो उठाएंगे।

अध्यक्ष जी, मैं आज एक मुद्दा दिल्ली सरकार के कर्मचारियों से संबंधित उठा रहा हूँ। अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो सेवारत हैं या सेवा-निवृत्त हैं, वो बहुत सारे कर्मचारी गुड़गांवा, फरीदाबाद, नोएडा, एन.सी.आर क्षेत्र में रहते हैं और वो दिल्ली सरकार से डी.जी.एच.एस की जो डिस्पेंसरी है उससे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हैं, वहीं से वो दवाइयां लेते हैं, वहां उनको आना पड़ता है। अध्यक्ष जी, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वृद्ध हैं, बीमार हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो दिल्ली में आते हैं, इससे उनके, बहुत उनको कष्ट भी होता है, खर्चा भी होता है, समय भी बर्बाद होता है तो मैं आपके माध्यम से महानिदेशक-स्वास्थ्य सेवाओं को मैं ये आदेश दिलवाना चाहता हूँ कि

कुछ ऐसा किया जाए कि एन.सी.आर क्षेत्र में भी हमारा स्वास्थ्य विभाग 3-4 डिस्पेंसरियां खोले, जिससे कि वो लोग, जो दिल्ली सरकार के कर्मचारी जो एन.सी.आर क्षेत्र में रहते हैं वो अपनी सभी चिकित्सा सुविधाएं वहां से ले सके और उनको दिल्ली न आना पड़े, उनको ये सारा का सारा खर्चा न उठाना पड़े। इस संबंध में अध्यक्ष जी मैं एक निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाओं के पत्र संख्या-38850, 38862 दिनांक 28 जुलाई, 2010 का भी मैं संज्ञान आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसमें बिंदु संख्या-7, 7.1 में इस तरह का प्रावधान का जिक्र भी किया गया है। तो अध्यक्ष जी जो ये अगर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए ऐसा किया जाएगा तो उनको बहुत सुविधा मिलेगी और इस संबंध में आपने जो मुझे ये बात रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः वीरेंद्र सिंह कादियान जी।

श्री वीरेंद्र सिंह कादियानः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जो मुझे बोलने का अवसर दिया। दिल्ली कैंट विधान सभा में अध्यक्ष महोदय बहुत से सरकारी कर्मचारी रहते हैं, जिसमें दिल्ली सरकार के कर्मचारी भी रहते हैं और जब भी मैं वहां जाता हूँ तो सरकारी कर्मचारी, वो एक ही बात कहते हैं कि आपकी जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, उन्होंने पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवाई तो दिल्ली के जो कर्मचारी है उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, 1 जनवरी, 2004 से न्यू पेंशन स्कीम केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए लागू कर दी गई थी। ये पेंशन स्कीम, जो न्यू पेंशन स्कीम है ये एक प्रकार से कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है और इसको एक मैनेजर के माध्यम से इसको इन्वेस्ट किया जाता है और बाजार के ऊपर निर्भर रहती है। अब इस पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी को जब वो सेवानिवृत्त होता है तो उस समय पता नहीं रहता कि इसको कितनी पेंशन मिलेगी, उस समय क्या स्थिति फाइनेंसियल देश की रहेगी, मार्केटों की रहेगी, और उस पैसे को जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो अगर छोटी सी भी गलती हो जाए, जैसे आज आप माहौल देख रहे हो, एक कंपनी जो बहुत ही hype कर गई थी और एकदम से धड़ाम से गिरी, ऐसी कंपनियों में अगर इन्वेस्ट कर दिया जाए पैसा, जैसे अडानी की कंपनी है मैं कहना चाहूँगा, इस प्रकार की कंपनियों में वो पैसा इन्वेस्ट हो जाए और एकदम से नीचे गिर जाए, क्योंकि विश्वास जब जनता का टूटता है तो शेयर मार्केट भी डगमगा जाता है, तो जिससे सरकारी कर्मचारी को बहुत बड़ा नुकसान होगा।

तो उस पेंशन स्कीम को बंद करके जो ओल्ड पेंशन स्कीम है जोकि, उसको ये, सरकारी कर्मचारी को ये पता रहता है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरी बेसिक पेंशन, सैलरी इतनी होगी और इस स्लेब में मेरी पेंशन बढ़ेगी और मैं आराम से अपना जीवन-यापन जब मैं सेवानिवृत्त होऊंगा 60 साल के बाद अपने बच्चों की देखरेख कर पाऊंगा और अपना जीवन-यापन अच्छी तरह कर पाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें समय-समय पर पे-कमीशन आने पर वो स्कीम के आधार पर पेंशन की भी बढ़ोतरी होती है, डी.ए जो है वो मिलता है उनको, जिससे उस पर फाइनेंसियल बोझ नहीं पड़ता, कर्मचारी पर।

क्योंकि आज का जो हिसाब देखें और उस पैसे का इन्वेस्टमेंट अगर गलत तरीके से हो जाए न्यू पेंशन स्कीम में तो सरकारी कर्मचारी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।

तो मेरा ये सदन में प्रस्ताव है अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि आप जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हैं, आप इस प्रस्ताव को यहां के इस सदन के माध्यम से वहां भी भेजें और जो दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें, जैसे हमने पंजाब में करी है। और इन सभी का, कर्मचारियों का श्री अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा है, ये ये ही कहते हैं कि अगर कोई कर सकता है ओल्ड पेंशन स्कीम अगर दिल्ली में लागू तो श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली के, वो ही कर सकते हैं क्योंकि वो जब हर तबके की आवाज सुन रहे हैं तो उनको सरकारी कर्मचारियों की भी इस मांग को मानने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और इसकी मंजूरी दिलानी पड़ेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया और सरकारी कर्मचारियों की आवाज उठाने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अंतिम, श्री विशेष रवि जी।

श्री विशेष रविः बहुत-बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी आपने नियम 280 के तहत मुझे अपनी विधान सभा क्षेत्र की समस्या को उठाने का मौका दिया। सर, हमारे यहां पर पिछले एक महीने से पानी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई हुई है। लगभग एक महीना होने वाला है कि हमारे क्षेत्र में विशेषकर नाई वाला, बीडन पुरा, जोशी रोड और पूरे पहाड़ गंज क्षेत्र के अंदर जो पानी पहले दो समय आता था वो एक समय आ रहा है और एक समय के अंदर भी जो है जो टैंक का लेवल है हमारा, जो 14 फिट के आसपास होता था वो अभी उससे भी कम हो रहा है। सर, सप्लाई का हमारे यहां पर ऐसा था कि एक दिन छोड़कर एक दिन शाम को सप्लाई होती है अलग-अलग क्षेत्र में, एक दिन करोल बाग में और एक दिन पहाड़ गंज के अंदर। और क्योंकि शाम की सप्लाई बंद है पूरी तरह से, तो सुबह भी जो लोग tail end पर रहते हैं, जिनके मकान पीछे हैं या फिर जो मकान, लंबी गलियां हैं और जिनके मकान सेंटर में पड़ते हैं उनको सुबह भी एक समय के अंदर भी पानी नहीं मिल रहा है। हम लगातार जल बोर्ड से बात कर रहे हैं लेकिन जल बोर्ड भी अपनी उसमें असमर्थता जाहिर कर रहे हैं क्योंकि वो बता रहे हैं, हम देख भी रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि हरियाणा से पानी की सप्लाई जो है बहुत कम हो रही है, जगह-जगह पानी को रोका हुआ है। सौरभ जी, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी है कि कैसे जो है हरियाणा के अंदर sand माफिया

के द्वारा जो है वो यमुना के ऊपर जो है पूरा पानी रोका हुआ है, ये हम पब्लिक को बता रहे हैं लेकिन सर पब्लिक भी बहुत दिन तक समझती नहीं है, वो ये बात को जो है मानने को तैयार नहीं होती।

अभी एक महीना हो गया है, तो मैं आज इस मौके पर आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि एल.जी साहब क्योंकि केंद्र सरकार के नुमाइंदे है, उनकी ये डयूटी बनती है कि वो अगर दो राज्यों में, हमारे यहां कोई समस्या बन रही है तो उनको हरियाणा सरकार से बात करनी चाहिए और इस समस्या का हल करना चहिए। मैं निवेदन करूंगा कि वो यहां इस मौके पर कुछ अपना प्रयास करें।

साथ-साथ में अपनी सरकार से भी निवेदन करूंगा क्योंकि ये समस्या अब हर साल की हो गई है। साल में चार-पांच महीने जो है पानी बहुत डिस्टर्ब होता है तो हमें भी कुछ न कुछ अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम हर बार जो है ये बोलकर कि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा है, उस पर नहीं छोड़ सकते पब्लिक को क्योंकि पब्लिक अब मानती नहीं, पब्लिक ये कहती है कि भई आपको जिम्मा है, जल बोर्ड आपके पास है तो समस्या का हल भी आप ही को करना पड़ेगा। तो सरकार से भी निवेदन है कि वो कुछ प्रयास करें। और साथ में मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें बहुत ज्यादा समय, एनर्जी की जरूरत है, तो अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो कुछ विधायकों की

डयूटी, कुछ projects wise जो है डयूटियां लगाये ताकि हम लोग जो हैं फॉलो-अप करने के लिए तैयार हैं। चंद्रावल प्लांट है, कोई और प्लांट है, जहां डयूटी लगायेंगे, हम लोग लगातार जो है क्योंकि समस्या हमारी है, हमसे ज्यादा जो है पैन इसमें कोई और नहीं लेगा, तो अगर माननीय मंत्री जी चाहें, ये सरकार चाहें तो कुछ काम बांटकर जो है हमारी डयूटी लगा दी जाए, हम जो हैं उस काम के फॉलो-अप के लिए हर रोज जो है पूछताछ कर लेंगे। आपने बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूँ आज कुल 21 ये 280 में चर्चाएं लगी थीं, 21 में से 17 टेकअप हो गईं, 3 सदस्य उपस्थित नहीं थे और एक किसी कारण रद्द करनी पड़ी है, शांतिपूर्वक सदन चलने का ये लाभ रहता है।

श्री राजेंद्र पाल गौतमः माननीय अध्यक्ष जी, एक छोटा सा, सर, एक सेकंड का, पूरे सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक गलती, असंवैधानिक काम इस सदन से हो रहा है अनजाने में या जानबूझकर, उसका सुधार, भूल-सुधार कर लें। हमारे यहां न्यूनतम मजदूरी 16,792 है और स्किल्ड की 20,357 है लेकिन हम सारे विधायकों के कार्यालय में डाटा एंट्री आपॅरेटर को हम 15,000 रूपये दे रहे हैं, ये कानून के खिलाफ है, इसको सुधार कर लिया जाए। बहुत धन्यवाद।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई झा साहब, ये, अगर कोई दिक्कत है, मुझसे बात कर लीजियेगा

माननीय अध्यक्षः नहीं मैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं प्लीज। झा साहब आप मुझसे आकर बात करिये। ...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ऐसा नहीं चल सकता बैठिये। मैं आपसे पूछ सत्ता पक्ष के 13 क्यों लगे?

माननीय अध्यक्षः इधार सुनिये, बात सुनिये, सत्ता पक्ष के 13 क्यों लगे। कौन चिंता करेगा इसकी? बैठिये। अब श्री सौरभ भारद्वाज जी माननीय शहरी विकास मंत्री अपने विभाग से संबंधित कार्यसूची के बिंदू क्रमांक 2 के उप बिंदु –1 में दर्शाये गए दस्तावेज की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

माननीय शहरी विकास मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची के बिंदु क्रमांक 2 के उप बिंदु –1 में दर्शाये गए दस्तावेजों की प्रतियां सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

1- दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के वर्ष 2020–21 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन (अंग्रेजी प्रति)[1]।

माननीय अध्यक्षः अब श्रीमती आतिशि जी माननीय ऊर्जा मंत्री अपने विभाग से संबंधति कार्य सूची के बिंदु क्रमांक 2 के उप

[1]दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या–23152 पर उपलब्ध।

बिंदु-2 में दर्शाये गए दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगी।

माननीय ऊर्जा मंत्री (श्रीमती आतिशी): अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची के बिंदु क्रमांक 2 के उप क्रमांक बिंदु-2 में दर्शाये गए दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ।

II- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी व अंग्रेजी प्रति)[2]

माननीय अध्यक्ष: सदन के प्रतिवेदन पर सहमति अब श्रीमती राखी बिरला, श्री दिलीप कुमार पाण्डेय जी प्रस्ताव करेंगे ''यह सदन दिनांक 17 मार्च, 2023 को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पांचवे प्रतिवेदन से सहमत है।''

श्रीमती राखी बिरला: अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यह सदन दिनांक 17 मार्च, 2023 को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पांचवे प्रतिवेदन से सहमत है।

माननीय अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में हैं वो हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं वो ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

---

[2]दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या-23153 पर उपलब्ध।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

माननीय कैलाश गहलौत जी, माननीय वित्त मंत्री, दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 प्रस्तुत करेंगे।

माननीय वित्त मंत्री (श्री कैलाश गहलौत): अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से दिल्ली की आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की हिन्दी तथा अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।[3]

माननीय अध्यक्ष: अब श्री गोपाल राय जी, माननीय विकास मंत्री उपराज्यपाल महोदय के.

माननीय वित्त मंत्री: दूसरा आउट कम बजट जो है उसकी रिपोर्ट पेश करिये।

माननीय अध्यक्ष: नहीं पहले तो आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़िये ना।

माननीय वित्त मंत्री: नहीं वो तो टेबल करना है ना।

माननीय अध्यक्ष: टेबल कर दिया, हो गया। ये मुझे दिया नहीं ना बाद में दिया। अब श्री कैलाश गहलौत जी, माननीय वित्तमंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आउट कम बजट 2022-23 की 31 दिसंबर, 2022 तक की स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

---

[3]दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या-23154 पर उपलब्ध।

उाउटकम बजट (2022-23)

माननीय वित्त मंत्री: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, टेबल करने से पहले अध्यक्ष जी मैं, ताकि सदन के सभी सदस्यों को थोड़ा अवगत करा सकूँ। मैं सदन के समक्ष इस सरकार का लगातार छठा आउट कम बजट रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहा हूँ।[4] इसमें 2022-23 के अंतर्गत 23 दिसंबर, 2022 तक की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों का विवरण है। अध्यक्ष जी लगातार हमारी सरकार ने जो शुरु किया था आउटकम और आउटपुट बजट को पेश करना और देश में शायद पहली सरकार है जो लगातार अपनी ही रिपोर्ट कार्ड जो है पब्लिक के बीच उसको पेश कर रही है, तो ये जो रिपोर्ट है, स्टेटस रिपोर्ट ऑफ आउटकम बजट 2022-23 ये मैं इस सदन के बीच आज रखा। महोदय दिल्ली का आउटकम बजट एक ऐसा अनूठा दस्तावेज है, जो जनता के पैसे से किये गए कामों की पारदर्शिता और जवाबदेही का उल्लेख प्रस्तुत करता है। बजट आबंटन अब केवल वित्तीय उपलब्धियों के रूप में नहीं मापे जाते बल्कि ये आउटपुट और आउटकम इंडीकेटर्स में विभाजित है। जिनका निरिक्षण अब बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। आउटकम बजट अब दिल्ली सरकार की हर प्रमुख स्कीम के दो प्रकार के इंडीकेटर्स के माध्यम से track किया जाता है। अध्यक्ष जी दो इंडीकेटर्स हैं जो हम usually इस पूरी रिपोर्ट में यूज करते हैं। पहला आउटपुट इंडीकेटर्स, जो सरकार के विभिन्न

[4]दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या-23155 पर उपलब्ध।

विभागों को द्वारा किये जा रहे कामों को ट्रैक करता है, जैसे कि कितने मौहल्ला क्लिनिक बने, कितने स्कूल बने इत्यादि और दूसरा जो इंडीकेटर हम यूज करते हैं इस पूरे रिपोर्ट में वो है आउटकम इंडीकेटर्स और आउटकम इंडीकेटर्स से हम ट्रैक करते हैं कि सरकार के कामों से लोगों को असलियत में कितना लाभ हुआ। जैसे कि हम स्कूल बनाते हैं या मौहल्ला क्लिनिक बनाते हैं तो वो तो आउटपुट इंडीकेटर का पार्ट है, लेकिन अगर हमने मौहल्ला क्लिनिक बनाया और उसमें सपोज पेशेंट्स ही नहीं आ रहे हैं तो उसको फिर हम आउटकम इंडीकेटर के साथ उसको ट्रेस करते हैं, कि मौहल्ला क्लिनिक में कितने मरीज चिकित्सा के लिए आए और उनमें से कितनों को मुफ्त दवाईयां मिलीं। सरकारी स्कूलों के छात्रों के कैसे परिणाम आये इत्यादि। केजरीवाल सरकार देश की पहली ऐसी राज्य सरकार है जो अपने कामों को लेकर तमाम आँकड़े स्वयं जनता के बीच रखती है। दिल्ली सरकार आउटकम बजट के तहत कुल एक लाख एक हजार एक सौ छत्तीस (1,01,136) इंडीकेटर्स से सरकारी कामों की निगरानी रखती है। इसमें 668 आउटपुट इंडीकेटर्स और 468 आउटकम इंडीकेटर्स शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्तमान वर्ष के आउटकम बजट के अंतर्गत जो मेजर अचीमेंट्स हैं उस पर प्रकाश डालूगां। सबसे पहले अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, तो इसमें टोटल जो इंडीकेटर्स थे वो 110 हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि 67 परसेंट जो इंडीकेटर्स हैं वो ऑन ट्रैक हैं। अगर हम key achievements की बात करें तो

सीबीएसई बोर्ड में दसवीं और बारहवी दोनों तरहों का परिणाम सराहनीय रहा। एकेडमिक सेशन 21-22 में सरकारी स्कूलों के बारहवीं का परिणाम 98 परसेंट और दसवीं का 97 परसेंट रहा। दिल्ली के 83 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। Directorate of Education के तहत 90 प्रतिशत से अधिक सरकारी स्कूल प्रतिदिन अपने छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कर रहे हैं। इसमें जो key achievements हैं अध्यक्ष जी चौथे नंबर पर सभी स्कूलों ने अपने पाठ्यक्रम में देशभक्ति पाठ्यक्रम को लागू किया। 2022-23 के दौरान मौजूदा स्कूलों में 11 नए Schools of Specialized Excellence जोड़े गए। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम में दो लाख छात्रों को दो हजार रुपये की सीड मनी प्रदान की गई, जिनसे 40 हजार से ज्यादा नए बिजनेस आइडियाज उत्पन्न हुए। अब मैं हैल्थ एण्ड फैमिली वैलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में जो इंडीकेटर्स हैं वो 124 टोटल इंडीकेटर्स हैं और उसमें से 54 परसेंट जो इंडीकेटर्स हैं वो ऑन ट्रैक हैं। हैल्थ डिपार्टमेंट की जो मेन मेजर जो key achievements है वो इस प्रकार है। 515 आम आदमी मौहल्ला क्लिनिक चालू हैं यहां रोजाना औसतन 21 हजार से ज्यादा मरीज इलाज कराने आते हैं। दिल्ली सरकार के 38 अस्पतालों में प्रतिदिन लगभग 63 हजार मरीजों ने आइपीडी में और 99 हजार मरीजों ने ओपीडी में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ उठाया। दिल्ली आरोग्य कोष योजना से 2,414 लोगों ने प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क इलाज प्राप्त किया। इसी योजना के प्रतिपूर्ती के तहत निजी

केन्द्रो पर 63,000 Radiological test की सिफारिश की गईं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट- अध्यक्ष जी टोटल जो इंडीकेटस हैं वो 88 हैं और 69 परसेंट जो इंडीकेटस हैं वो ऑन ट्रैक हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अगर कुछ हम key achievements के बारे में अगर हम बात करें तो सभी सार्वजनिक सेवाओं को फेसलेस तरीके से प्रदान करने के लिए प्रमुख पहल शुरू की गईं इसमें अब तक 23 लाख से अधिक अनुरोध का समाधान किया गया है। ये जो 35 लाख जो सर्विसेस हैं अध्यक्ष जी ये टोटल हमने फेसलैस तरीके से इनको resolve किया है। दिसम्बर 2022 तक 93 हजार E-vehicles जो हैं उनका रजिस्टेशन हो चुका है। दिसम्बर 2022 में दिल्ली में बेचे गए सभी वाहनों में इलैक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 16.7 प्रतिशत थी अध्यक्ष जी जो भारत में किसी भी राज्य से अधिक है। वन दिल्ली ऐप नवम्बर 2022 में लांच हुआ इस ऐप पर 3,300 कलस्टर बसें और 4,000 डीटीसी बसों को ट्रैक किया जा सकता हैं। हमारी सभी कलस्टर buses में बस मार्शल तैनात हैं और डीटीसी बसों में 92 परसेंट buses में बस मार्सल्स तैनात हैं। अब पीडब्लुडी के टोटल इंडीकेटस जो हैं वो 60 हैं और इसमें से 77 परसेंट जो इंडीकेटस हैं वो ऑन ट्रैक है। अगर हम key achievements की अगर अध्यक्ष जी बात करें पीडब्लुडी के तो आपको अध्यक्ष जी याद होगा कि हमने वादा किया था कि पूरी दिल्ली में विशाल जो हैं तिरंगे झण्डे लगाये जायेंगे और 500 ऊंचे विशाल झण्डे पूरी दिल्ली में लगे और दिल्ली आज के दिन तिरंगों का शहर बन गया है। आम जनता की

सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर 2 लाख 6 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं। आश्रम फ्लाईओवर से डीएनडी फ्लाईओवर तक फ्लाईओवर के विस्तार का काम पूरा हो चुका है। दिल्ली की सड़कों पर यूरोपीय सड़कों की तर्ज पर जो 16 स्ट्रैच हैं उन पर काम पूरा हो रहा है।

जल बोर्ड- जलबोर्ड के टोटल इंडीकेट्स इंडीगेटर 61 हैं और उनसे 66 परसेंट इंडीकेटर्स ऑन ट्रैक हैं। जल बोर्ड की कुछ key achievements हैं, 2021-22 में 929.13 एमजीडी का हमारे यहां पानी का प्रोडक्सन था और वो 2022 में अब 995 हो गया है। लगभग 65 एमजीडी का प्रोडक्सन बढ़ा है अध्यक्ष जी। दिल्ली जलबोर्ड के 27 लाख 34 हजार जो कंज्युमर्स हैं उनमें 73 परसेंट घरेलु कंज्युमर्स को पानी की सब्सिडी मिल रही है। अनॉथराइज कॉलोनी में जो बिछाई गई पानी की पाइप लाइन की लम्बाई बढ़कर 5 हजार 300 किलोमीटर कर दी गई है। अब 97 प्रतिशत अनॉथराइज कॉलोनियों में पाइप लाइन से जल आपूर्ति हो रही है। गुणवत्ता के लिए लगभग 16 हजार पानी के सेम्पल का टेस्ट किया गया है। इसमें 97 परसेंट sample मानकों पर खरे पाये गए हैं। Woman and Child Department अध्यक्ष जी टोटल इंडीकेटर्स 68 हैं और इसमें 71 परसेंट इंडीकेटर्स जो हैं वो ट्रैक पे हैं। Woman and Child की जो key achievements हैं डिपार्टमेंट की 2022-2023 में लगभग 3 लाख 47 हजार महीलाओं को मासिक वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 35 हजार से

अधिक है। 6 लाख 38 हजार बच्चे और गर्भवती महीलायें, मातायें आंगनबाड़ियों के माध्यम से पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवायें प्राप्त कर रही हैं। लाडली योजना के तहत 31 हजार 743 लड़कियों का नामांकन हुआ। वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही तक लगभग 21 हजार maturity cases का भुगतान किया जा चुका है।

अध्यक्ष जी नेस्ट जो Environment and Forest Department- इसके 79 टोटली इंडीकेटर्स हैं और 73 परसेंट इंडीकेटर्स जो हैं ऑन ट्रैक हैं। कुछ मेजर जो अचीवमेंट्स रहीं इसमें जो polluting units हैं उसका लगातार ऑन लाइन मेनेजमेंट और मॉनिटरिंग चल रही है। वन क्षेत्र में 10 लाख 78 हजार पौधो लगाये गए हैं। प्रदूषण विरोधी मानदंडों की उल्लंघन की ग्रीन दिल्ली ऐप पर आई 75 परसेंट शिकायतों का निर्धारित समय अवधिा के भीतर समाधान किया गया है। प्रदूषण के विभिन्न कारणों की रियल टाइम पर पहचानने के लिए आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और T.E.R.I. के सहयोग से आधुनिक लैबस्थापित की गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट के टोटल इंडीकेटर्स अध्यक्ष जी 13 हैं और इसमें से 77 परसेंट जो इंडीकेटर्स हैं वो ऑन ट्रैक हैं। कुछ की अचीवमेंट्स एआर डिपार्टमेंट की सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी के तहत 82 हजार 684 सर्विस request को पूरा किया गया है। पीजीएमएस के तहत प्राप्त 96,000 शिकायतों में से 84 हजार शिकायतों का निवारण किया गया है। आरटीआई के माध्यम से लगभग 38 हजार आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से लगभग 24 हजार को 30 दिनों के भीतर resolve

किया गया है। अध्यक्ष जी ये ही मेन अचीवमेंट्स हैं आउटकम और आउटपुट बजट की। अध्यक्ष महोदय दिल्ली का व्यापक आउटकम बजट पूरे देश में एक अनूठी बजटीय पहल है। यह न केवल आम लोगों हमारे विभागों के लिए प्रभावित दस्तावेज है, बल्कि परियोजना को और बेहतर कैसे बनाया जाए इसका अधयन करने वाले रिसर्चर के लिए भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है। ये माननीय मंत्रियों एवं उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर स्कीम कार्यक्रमों की प्रगति की ट्रेकिंग के लिए एकप्रभावी साधान है। इस पहल को प्रभावशाली बनाने के लिए योजना विभाग ने डायलोग और डवलपमेंट कमिशन ऑफ़ दिल्ली के समर्थन से एक आउटकम बजट डेसबोर्ड में विकसित किया है। डेसबोर्ड से अध्यक्ष जी जो उसका main advantage होगा कि आप रियल टाइम में और कम समय में जितने भी हमारे indicators हैं आप उनको ट्रैक कर सकेंगे और जान सकेंगे कि कौन-सा डिपार्टमेंट किस लेवल पे परफ़ोर्म कर रहा है। जो सभी योजना पर रियल टाइम निगरानी रखने और पूरी प्रक्रिया को डिजीटल बनाने में सक्षम होगा। यह आउटकम बजट की प्रभावशीलता को और बढ़ायेगा। आउटकम बजट 2023-24 तैयार करने का प्रयास योजना विभाग द्वारा जल्द ही शुरू किया जाएगा। आउटकम बजट की कॉपी सभी माननीय सदस्यों को भेजी जायेगी। इसे योजना विभाग के बेवसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः अब श्री गोपाल राय जी माननीय विकास मंत्री उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

माननीय विकास मंत्री (श्री गोपाल राय): माननीय अध्यक्ष महोदय दिल्ली के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां हैं उनमें मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि यह सदन दिनांक 17 मार्च 2023 को उपराज्यपाल महोदय द्वारा विधान सभा को दिये गए अभिभाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। अध्यक्ष महोदय आभार व्यक्त करने के साथ आज सदन के अंदर जिस तरह से माननीय उपराज्यपाल महोदय ने सरकार के कामों का वर्णन किया, अध्यक्ष महोदय अरविन्द केजरीवाल के नेतश्त्व में दिल्ली में सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन इस बार की जो विशेष परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में दिल्ली के माननीय उप राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण रखा उस अभिभाषण के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार द्वारा किये जा रहे कामों में जिस तरह की अड़चनें पैदा हो रही हैं उन अड़चनों के बावजूद दिल्ली के अंदर सरकार ने जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में अपने काम को जारी रखा है वो काबिल-ए-तारीफ है। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय वित्त मंत्री अभी आउटकम बजट ये हमारे सदन के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से निरन्तर कार्य हो रहा है हम तमाम देखते

हैं राजनीति में तमाम सरकारें आई, गई राज्यों के अंदर, केन्द्र के अंदर उन सरकारों का जो लक्ष्य होता है वो चुनाव को लेकर के होता है। चुनाव जब आ रहा होता है तो सरकारें बहुत सारे काम करती है और जब चुनाव खत्म होता है तो सरकारें सारे अपने एजेंडे को ठंडे बस्ते में डाल देती है। लेकिन मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी को इस सदन के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ कि पहली बार सरकार बनने के बाद से और आज तक निरन्तर दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में चाहे बजट का मामला हो, चाहे नए नए पाठयक्रम का मामला हो, चाहे पूरी दुनिया के अंदर से जो भी अच्छी चीजें उनको सीखकर के दिल्ली के अंदर इंप्लीमेंट करने का मामला हो हर साल दिल्ली की शिक्षा क्रांति एक एक कदम नये कीर्तिमान को स्थापित कर रही है अध्यक्ष महोदय। आज हमें इस बात का अफसोस भी है अध्यक्ष महोदय कि न सिर्फ दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर पूरी दुनिया के अंदर शिक्षा क्रांति के जनक आज मनीष सिसोदिया हमारे बीच में नहीं हैं और उस शडयन्त्र की वजह से नहीं हैं। दिल्ली के अंदर अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली के अंदर जो प्राईवेट स्कूल हैं जहां एक लाख, दो लाख, चार लाख, दस लाख, बीस लाख रूप्ये डोनेशन लगते हैं जिन स्कूलों में बड़े से बड़े डोनेशन के बाद एडमिशन होता है अध्यक्ष महोदय इस सदन को इस बात का गर्व है कि दिल्ली के अंदर जो सबसे महंगे स्कूल हैं उनसे

भी बेहतर रिजल्ट आज सरकारी स्कूल के बच्चे लेकर के आ रहे हैं ये कीर्तिमान स्थापित किया है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर शिक्षा आज सब जानते हैं कि पूरे देश ने इस बात को मान लिया था कि सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं किया जा सकता। गरीब जो अपने बच्चों को मजबूरी में इस सरकारी स्कूल में एडमिशन कराता था अध्यक्ष महोदय, जब घर पे कोई रिश्तेदार आता था पूछता था कि बच्चे कहां पढ़ते हैं वो बताने में शर्म महसूस करता था। लेकिन आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जिन गार्जियन के बच्चे पढ़ते हैं आज रिश्तेदारों को ही नहीं, अपने जो भी जानकार हैं उन सबको इस बात को गर्व से बताते हैं हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है दिल्ली के। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर जिस तरह से न सिर्फ पढ़ाई का बल्कि पढ़ाई का लोगों की जिंदगी से क्या संबंध बने क्योंकि मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, भारत के अंदर आजादी के बाद जब शिक्षा नीति बन रही थी तो देश के स्वतंत्रता आंदोलन के जननायक महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम की बात रखी थी और उस में इस बात पर जोर था कि शिक्षा बेरोजगारों को पैदा करने की फैक्टरी न बन जाये। धीरे धीरे कालांतर में वो चीजें डेवलप हुई लेकिन पहली बार दिल्ली के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ साथ जिस तरह से बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम को शुरू करके छात्रों को जिस तरह से उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए आत्मनिर्भर बनाने की पूरी मुहिम शुरू हुई है अध्यक्ष महोदय ये अद्वितीय है। भारत के अंदर किसी भी देश

के अंदर सरकारी विद्यालय के अंदर ये अभियान नहीं चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था है दिल्ली की अर्थव्यवस्था पे प्रतिव्यक्ति जो आय वो लगभग 17 परसेंट की वृद्धि हुई है। पिछले सालों के मुकाबले में अध्यक्ष महोदय स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज की तारीख में दिल्ली के अंदर 522 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर एक नये तरह का प्रयोग है। दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य को लेकर के न सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक बल्कि दिल्ली के अंदर 16 हजार नये बेड अलग अलग अस्पतालों में जोड़े गए हैं। दिल्ली के अंदर सामाजिक सुरक्षा के मामले में भी सरकार ने हर क्षेत्र के लोगों के प्रति अपना संवेदना और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। दिल्ली के लोगों को बिजली के क्षेत्र में जो सुविधा मिल रही है अध्यक्ष महोदय माननीय उप राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में रेखांकित किया। हमें याद है कि जब दिल्ली के अंदर पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो हमारा एक नारा होता था कि आम आदमी पार्टी की सरकार आयेगी तो बिजली का बिल हाफ होगा और पानी का बिल माफ होगा। अध्यक्ष महोदय वादा किया था इस सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि बिजली का बिल हाफ होगा। पहली सरकार है जिसने वादा तो हाफ का किया था लेकिन आज 200 यूनिट माफ है दिल्ली के अंदर। वादे से भी ज्यादा काम करने वाली सरकार का नाम है अरविंद केजरीवाल की

सरकार। अध्यक्ष महोदय 200 यूनिट तक आज दिल्ली के लोगों को बिजली फ्री मिल रही है जिनका खर्च है 400 यूनिट जिनका खर्च है उनको आधे पे मिल रही है। अध्यक्ष महोदय परिवहन के क्षेत्र में जिस तरह से आज दिल्ली के अंदर दिल्ली के परिवहन को संचालित करने के लिए नए बसों का बेड़ा जुड़ रहा है लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली जिस तरह से EV पॉलिसी के माध्यम से देश की केपिटल बन रही है परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों के जुड़ने के साथ साथ दिल्ली के अंदर लोगों में जो प्राईवेट गाडियां लेने में भी जिस तरह की पालिसी सरकार लेकर आई है उसमें लोगों के अंदर एक पैशन दिख रहा है उसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर बिजली पानी, स्कूल, अस्पताल के साथ साथ पर्यावरण एक अहम मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय इस सदन को माननीय उप राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सूचित किया और मैं पूरी दिल्ली के लोगों को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूँ कि आज दिल्ली में दिल्ली के लोगों के प्रयास से दिल्ली के अंदर अगर हम पिछली बार की देखें तो दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन का स्तर है वो लगातार गिर रहा है। दिल्ली के अंदर जो सीवियर डेज़ होते थे 2018 में जो सीवियर डेज़ थे उन सीवियर डेज़ के मुकाबले में 28 के मुकाबले में इस बार केवल 3 दिन ऐसा रहा है जो सीवियर केटेगरी में रहा है। दिल्ली का पीएम 2.5 दिल्ली का पीएम 10 में लगातार गिरावट महसूस की जा रही है। साथ ही साथ दिल्ली के लोगों के प्रयास से आज दिल्ली का जो ग्रीन बेल्ट है वो लगातार बढ़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से जो तथ्य हमारे सामने आये, उन तथ्यों के आधार पर दिल्ली के इन विपरित परिस्थितियों में एक ही बात अपनी बात कहके समाप्त करना चाहता हूँ - वो हमें परेशान करते रहेंगे और हम मिलकर के काम करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, शुक्रिया।

श्री ऋतुराज गोविंदः अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी.

माननीय अध्यक्षः भई वो बोल रहे हैं एक बार।

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष जी, आपकी परमीशन चाहता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण मुददे को रखने के लिए और बहुत संवेदनशील मुददा है। अध्यक्ष जी, जैसा कि पूरी दिल्ली नहीं पूरे देश को पता है कि किस प्रकार से दिल्ली की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतश्त्व में दिल्ली की शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं लेकिन अध्यक्ष जी इस देश की डेमोक्रेसी में इस देश के लोकतंत्र में कल एक ऐसा काला दिन था के जब कुछ भाजपा के लोगों ने मिलकर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब रोहिणी के एक स्कूल में गए जो स्कूल था माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के जो स्कूलों में school of excellence स्कूल हैं उनका नाम डॉ. बी. आर. अंबेडकर के नाम पर रखा है। अध्यक्ष जी, ये बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने

इस देश को संविधान दिया उनके सम्मान में दिल्ली के उन स्कूलों का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखा गया है लेकिन अध्यक्ष जी कल रोहिणी सैक्टर 18 के एक स्कूल के अंदर रोहिणी सैक्टर 18 के एक स्कूल के अंदर भाजपा के लोगों ने अध्यक्ष जी बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया इन लोगों ने और बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने के बाद इन लोगों ने आज उनको अपमान करने का काम किया और साथ-साथ मनीष सिसोदिया जी को जेल में डालने का काम किया अध्यक्ष जी, जिन्होंने बाबा साहब के नाम पे स्कूल का नाम रखा उनको जेल में डालने का काम किया मनीष सिसोदिया जी को, ये उस मानसिकता के लोग हैं

(सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्य नारे लगाते हुए वैल में आ गए)

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष जी, इन लोगों ने केवल और केवल बाबा साहब का अपमान किया और साथ में जिन्होंने शिक्षा में अच्छा काम किया उनको जेल में डालने का काम किया।

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ अपने-अपने स्थान पर बैठें।

...व्यवधान...

. माननीय सदस्यों से प्रार्थना है अपने-अपने स्थान पर बैठें। ये सैक्रेट्री साहब की कुर्सी छोड़िए। हाउस एक बजे तक के लिए

ऐडजोर्न किया जाता है। हाउस एक बजे तक ऐडजोर्न किया जाता है।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 1 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

सदन अपराह्न 1.00 बजे पुनः समवेत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

श्री ऋतुराज गोविंदः अध्यक्ष जी, देश के सबसे बड़े शिक्षा मंत्री अध्यक्ष जी मनीष सिसोदिया जी जिन्होंने शिक्षा का महत्व दुनिया को दिखाया।

...व्यवधान...

श्री ऋतुराज गोविंदः उसको जेल में डालने, झूठे शडयंत्र

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ हाउस का जो बिजनैस है उसको चलने दें। माननीय सदस्य गण अपने-अपने स्थान पर बैठें।

...व्यवधान...

(सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्य नारे लगाते हुए वैल में आ गए)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ अपने–अपने स्थान पर बैठें। माननीय सदस्य गण अपने–अपने स्थान पर बैठें।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य गण अपने–अपने स्थान पर बैठें। माननीय सदस्य गण कश्प्या अपने–अपने स्थान पर बैठें, हाउस की कार्रवाई चलने दें।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हाउस की कार्रवाई कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही दिनांक 21 मार्च, 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।